एल. सी. हनुमंथप्पा (मृतक) जरीये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

एच. बी. शिवाकुमार

(2015 की सिविल अपील No.6595)

26 अगस्त, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

परिसीमा अधिनियम, 1963-अनुसूचित अनुच्छेद 58-मूल लिखित कथन में (16 पर दायर)-9.3.1990 पर दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मूल वाद-संशोधित वाद पर लागू होना। 5. 1990) संपत्ति के लिए वादी के अधिकार से इनकार किया गया-दिनांक 28.3.2002 के आदेश द्वारा अनुमत वाद का संशोधन-वाद अनुसूचित संपत्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद का संशोधन-अतिरिक्त लिखित बयान में कि स्वामित्व की घोषणा की याचिका समय-बाधित थी-मुकदमे का आदेश दिया गया, परिसीमा की याचिका को खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने माना कि संशोधित याचिका समय-बाधित थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने का अधिकार पहली बार 16.5.1990 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में टाइटल से इनकार किया - 16.5.1990 से 3 साल बाद किया गया संशोधन धारा के तहत समय-बाधित था। 58- संबंध वापसी का सिद्धांत भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि संशोधन की अनुमति परिसीमा के अनुरोध के अधीन दी गई थी- संबंध वापसी का सिद्धांत- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 6 नियम 17.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 58 संशोधित वाद पर उतना ही लागू होगा जितना कि यह स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए पहले से मौजूद राहत में स्वामित्व की घोषणा की राहत को जोड़ने का प्रयास करता है। वाद का वर्तमान संशोधन वास्तव में समय-बाधित है क्योंकि स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने का अधिकार पहली बार 16 मई, 1990 को उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिवादी ने पहले ही लिखित बयान में दलील दी थी कि निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए मुकदमा इस मायने में बनाए रखने योग्य नहीं है कि वादी मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने में विफल रहा था। [पैरा 13,14] [660-ए-बी; 662-ई-एफ]

खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2011 (15) एससीआर 299: (2011) 9 सेक 126-पर निर्भर था।

2.1 वर्तमान मामले में दो बातें स्पष्ट हैं। सबसे पहले, 16 मई, 1990 के मूल लिखित बयान में, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वादी को नोटिस पर रखा था कि उसने वाद संपत्ति पर वादी के अधिकार से इनकार कर दिया था। दूसरा; संशोधन की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने 28 मार्च, 2002 के अपने पहले के फैसले में मामले को स्पष्ट रूप से निचली अदालत में भेज दिया था, जिससे प्रतिवादी को परिसीमा की याचिका उठाने की अनुमति मिल गई थी। इस प्रकार, स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने का अधिकार पहली बार 16 मई, 1990 को उत्पन्न हुआ जब मूल लिखित बयान ने स्पष्ट रूप से वादी के अधिकार से इनकार कर दिया। इसलिए 16 मई, 1993 तक स्वामित्व की घोषणा पर आधारित मुकदमा समय-बाधित हो जाता। [पैरा 29] [67 4-ए-ई]

2.2 संबंध वापसी का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस कारण से लागू नहीं होगा कि जिस न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी थी, उसने स्पष्ट रूप से

इसकी अनुमति दी थी, जो परिसीमा की याचिका के अधीन थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान मामले में संबंध वापसी के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई विशेष या असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं ताकि प्रतिवादी के पक्ष में अर्जित कानूनी अधिकार को छीन लिया जाए। [पैरा 29] [674-ई-एफ]

किसानदास रूपचंद बनाम रचप्पा विठोबा आईएलआर 33 बॉम्बे 644 (1900); पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल 1957 एससीआर 595; चरण दास बनाम अमीर खान 47 आईए 255 (1920); एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डिन स्किनर एंड कंपनी 1957 एससीआर 438; के. रहेजा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और अन्य बनाम गठबंधन मंत्रालय और अन्य, 1995 (3) एस. सी. आर. 960:1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 17; विश्वंभर और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण (मृत) LRs व अन्य के माध्यम से, (2001) 6 एस. सी. सी. 163; सिद्दलिंगम्मा और अन्य बनाम ममता शेनॉय 2001 (4) पूरक एस. सी. आर. 366: (2001) 8 एस. सी. सी. 561; संपत कुमार बनाम अय्याकन्नु और अन्य 2002 (2) पूरक एस. सी. आर. 397: (2002) 7 एस. सी. सी. 559; वन विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादा सी. (पंजीकृत) बनाम रमेश चंदर और अन्य 2010 (12) एस. सी. आर. 1045 (2010) 14 एस. सी. सी. 596; पृथ्वी पाल सिंह और अनार बनाम अमरीक सिंह और अन्य। (2013) 9 एस. सी. सी. 576-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2011(15)एससीआर 299	पर भरोसा किया	पैरा 13
आईएलआर 33 बॉम्बे644(1900)	संदर्भित किया गया	पैरा 15
1957 एससीआर 595	संदर्भित किया गया	पैरा 16
47 आई ए 255 (1920)	संदर्भित किया गया	पैरा 17

1957 एससीआर 438	संदर्भित किया गया	पैरा 18
1995(3) एससीआर 96	संदर्भित किया गया	पैरा 22
(2001) 6 एससीसी 163	संदर्भित किया गया	पैरा 23
2001(4) पूरक एससीआर 366	संदर्भित किया गया	पैरा 24
2002 (2) पूरक एससीआर 397	संदर्भित किया गया	पैरा 25
2010 (12) एससीआर 1045	संदर्भित किया गया	पैरा 27
(2013) 9 एस.सी.सी.576	संदर्भित किया गया	पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2015 की सिविल अपील संख्या 6595

2009 के आर. एफ. ए. सं. 796 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 05/03/2015 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए पी. विश्वनाथ शेट्टी, एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, महेश ठाकुर, अंकुर एस. कुलकर्णी।

प्रतिवादी के लिए डॉ. आदित्य सोंधी, चंदन एस. राव, विकास मेहता, अनुश्री मेनन।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दे दी गई।

2. वर्तमान मामला पक्षों द्वारा दायर क्रॉस मुकदमों से उत्पन्न होता है। 9 मार्च, 1990 को एक एल. सी. हनुमंतप्पा ने एक एच. बी. शिवकुमार के खिलाफ प्रतिवादियों, उनके सेवकों और एजेंटों को मुक़दमा अनुसूचित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में बाधा डालने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष दायर किए गए 1990 के ओ. एस. नंबर 1386 नामक

इस मुकदमे में, वादी ने दावा किया कि वह पूर्ण मालिक है, और मुकदमे की संपत्ति के कानूनी कब्जे और आनंद में है। उन्होंने उक्त मुकदमे में यह भी कहा कि अनुसूचित संपत्ति स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य है और इसे बिना किसी कठिनाई के पहचाना जा सकता है। वादी के अनुसार, कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने मुकदमा दायर होने से दो दिन पहले अनुसूचित संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की।

3. यह मुकदमा दायर होने के कुछ दिनों के भीतर, पहले मुकदमे में प्रतिवादी ने एक एल. सी. के खिलाफ बैंगलोर के सिटी सिविल कोर्ट में 1990 का मुकदमा संख्या ओ. एस. 1650 होने का मुकदमा दायर किया। रमैया और उक्त श्री हनुमंतप्पा ने कहा कि प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर होने से लगभग 15 दिन पहले मुकदमा अनुसूचित संपत्ति में अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, और उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, जिसमें उन्हें मुकदमा अनुसूचित संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से रोका गया था। वादी ने मुकदमा अनुसूचित संपत्ति के कब्जे में मालिक होने का भी दावा किया।

4. 16 मई, 1990 के ओ. एस. सं. 1386 को दिए गए लिखित बयान में, प्रतिवादी ने न केवल अपने स्वयं के मुकदमे का उल्लेख किया जो तब तक पहले ही दायर किया जा चुका था, बल्कि विशेष रूप से निम्नानुसार कहा गया थाः -

> "4. वादी द्वारा शिकायत अनुसूचित में पुरानी सर्वेक्षण साइट No.13 को दी गई परिसीमाएँ पूरी तरह से गलत हैं और इसका उसके दस्तावेज़ में उल्लिखित परिसीमाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

5. वादी पुरानी साइट No.13 और निगम No.12/2 के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है, जैसा कि उसने शिकायत में दावा किया है।

6. यह आरोप कि वादी द्वारा अनुसूचित संपत्ति की खरीद के समय, पश्चिमी परिसीमा एक इमारत स्थल थी जिस पर No.14 था और हालांकि बाद में निर्माण स्थल के लिए छोड़े गए उक्त हिस्से को सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और कई वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है, गलत है और आगे यह कहना गलत है कि अनुसूचित संपत्ति वाली इमारत स्थल संख्या 12 का पूर्व स्थित है और वह एक एच. वेंकटरमनप्पा का था और हालाँकि, उक्त स्थान उसके द्वारा बेचा गया है और अब उक्त संपत्ति एक श्री अहमदुल्ला खान के स्वामित्व में है और उसने उस पर एक इमारत का निर्माण किया है, जैसा कि शिकायत के पैरा 2 में आरोप लगाया गया है।

7. वादी ने अपनी पुरानी साइट संख्या 13 को जानबूझकर विकृत कर दिया है ताकि साइट No.15, पुरानी 3, सी. टी. एस. संख्या 1157 (शहर सर्वेक्षण) की परिसीमाओं को काफी हद तक लाया जा सके जो विशेष रूप से प्रतिवादी की है।

13. निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा इस मायने में बनाए रखने योग्य नहीं है कि वह साइट संख्या पुरानी 13 पर अधिकार स्थापित करने में विफल रहा है, और यह पुरानी साइट No.13 और नई संख्या 12/2 के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, जिसे कथित रूप से बैंगलोर नगर निगम या लगभग 6-6-1989 द्वारा सौंपा गया है।"

5. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 16 मई, 1990 को ही 1990 के ओ. एस. सं. 1386 में वादी को नोटिस पर रखा गया था कि निषेधाज्ञा के लिए उनका मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि वह वाद अनुसूचित संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने में विफल रहा था।

6. दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ की गई और 1 मार्च, 1999 के एक फैसले द्वारा बैंगलोर में अतिरिक्त शहर सिविल न्यायाधीश की अदालत ने 1990 की ओ. एस. संख्या 1650 का आदेश दिया और 1990 की ओ. एस. संख्या 1386 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के खिलाफ दायर पहली अपीलों में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक आई. डी. 1,2002 के फैसले द्वारा 1999 के आर. एफ. ए. संख्या आई. डी. 2 की अनुमति दी, और 1999 के आर. एफ. ए. संख्या 456 को खारिज कर दिया, और मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय ने मामले को रिमांड पर लेते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "10. निचली अदालत ने आयुक्त की भी नियुक्ति की थी। आयुक्त ने संपत्तियों का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। आयुक्त से पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में भी पूछताछ की गई है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि विवाद दो संपत्तियों की पहचान और संपत्तियों पर अधिकार और स्वामित्व घोषित करने के संबंध में है। इस मामले में प्रत्यर्थी ने उस बिक्री विलेख पर विवाद नहीं किया है जो अपीलार्थी के नाम पर है। चूंकि प्रतिवादी विवाद कर रहा है और सूट अनुसूचित संपत्ति का अस्तित्व है, इसलिए वर्तमान आवेदन उसके अधिकार की घोषणा के लिए दायर किया जाता है। प्रत्यर्थी ने यह तर्क देते हुए आवेदन का विरोध किया है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत परिसीमा द्वारा वर्जित है और वह राहत

परिसीमा के माध्यम से मांगी गई है। हालाँकि, इस तरह की याचिका उत्तरदाताओं द्वारा अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके उठाई जा सकती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक अचल संपत्ति के संबंध में विवाद और दो संपत्तियों की पहचान का सवाल शामिल किया गया है, क्योंकि प्रतिवादी भी अपीलार्थी के बिक्री विलेख पर विवाद नहीं कर रहा है, यह अदालत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने के लिए याचिका में संशोधन के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की मांग करती है।

11. तदनुसार, आर. एफ. ए. संख्या 415/99 की अनुमति है। ओ. एस. सं. 1386/90 में पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है। दोनों पक्षों को उचित अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से जांच करने के लिए निचली अदालत को भेज दिया गया है। प्रतिवादी अतिरिक्त लिखित बयान दायर करने का हकदार है और परिसीमा का सवाल उठाने का भी हकदार है। विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आज से छह (6) महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करेगा। ओ. एस. 1650/90 में पारित निर्णय और डिक्री, जो आर. एफ. ए. 415/99 की विषय वस्तु है, का संबंध है, इस अदालत को निषेधाज्ञा की डिक्री को बाधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि ओ. एस. 1386/90 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित की जाने वाली डिक्री का ओ. एस. संख्या 1650/90 के फैसले और डिक्री पर असर पड़ेगा। ओ. एस. 1386/90 में अपीलार्थी के सफल होने की स्थिति में, केवल निषेधाज्ञा के लिए शिवकुमार के पक्ष में ओ. एस. 1650/90 में पारित निर्णय और डिक्री अपीलार्थी-हनुमथप्पा के

खिलाफ अप्रवर्तनीय होगी। हालाँकि, यह धारा 1386/90, के निपटान तक स्पष्ट किया जाता है। ओ. एस. 1650/90 में प्रतिवादी/वादी-शिवकुमार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। यदि ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी/वादी-शिवकुमार निर्माण के साथ आगे बढ़ सकते हैं और यदि उन्हें निर्माण करने की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी ओ. एस. सं. 1386/90 में सफल हो जाता है, तो इससे कई कार्यवाहियां होंगी। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तरदाताओं को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।

7. 1 अप्रेल 2002 को, वादी ने ओ.एस. संख्या 1386/1990 में वाद पत्र में पैरा 5 ए जुड़वाकर संशोधन कराना चाहा, जिसमें बताया गया कि-

"5A वादी यह कथन करता है कि प्रतिवादी का वादग्रस्त सम्पत्ति में कोई स्वामित्व या हित नहीं है। प्रतिवादी ने वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में वादी के स्वामित्व से इंकार किया है, इसलिए वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी व कब्जेधारक है, इसकी घोषणा कराया जाना उचित व आवश्यक है। यदि वादी को वांछित घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया गया तो वादी, जो कि 05-05-1956 से वादग्रस्त सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी होकर उपयोग-उपभोग कर रहा है, को गंभीर क्षति और पूर्वाग्रह कारित होगा। इसके विपरीत घोषणा का अनुतोष दिये जाने पर प्रतिवादी को कोई क्षति या पूर्वाग्रह कारित नहीं होगा।"

8. वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामित्व के उद्घोषणा की डिक्री प्रदान करने का अनुतोष संशोधित वाद में 01 अगस्त 2002 को जोड़ा गया, तो प्रतिवादी ने एक अतिरिक्त लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी ने कथन किया कि उक्त

अभ्युक्ति, स्वामित्व की घोषणा, नये वाद कारक पर आधारित है, जो कि अवधि बाधित है।

9. रिमाण्ड किये जाने के बाद, सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलौर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांकित 16-04-2009 द्वारा ओ.एस. नंबर 1386/1990 को डिक्री किया। परिपरिसीमा की आपत्ति को नहीं मानते हुए यह माना कि चूंकि मूल लिखित कथन में ही प्रतिवादी ने वादी हनुमंथप्पा के स्वामित्व को स्वीकार किया है और बाद में केवल 01-08-2002 में प्रथम बार संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व से इंकार किया है। ऐसे में वादी द्वारा चाहा गया घोषणा का अनुतोष परिपरिसीमा अवधि के अंतर्गत ही है।

10. उच्च न्यायालय ने आर.एफ.ए. संख्या 796/2009 में चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांकित 5 मार्च 2015 में यह माना कि इस मामले में दिनांक 16 मई 1990 को प्रस्तुत मूल लिखित कथन में ही स्पष्ट रुप से यह बताया गया था कि वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी के पास आवश्यक स्वामित्व नहीं है। चूंकि वाद पत्र में संशोधन दिनांक 16 मई 1990 से तीन वर्ष की लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह स्पष्ट था कि यह परिपरिसीमा बाधित था। इस प्रकार 1990 के ओ. एस. सं. 1386 को केवल परिपरिसीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने परिपरिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 के संदर्भ में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर परिसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वर्तमान मामले में दोषपूर्ण कृत्य निरंतर दोषपूर्ण कृत्य की श्रेणी में नहीं था।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार शिकायत में संशोधन की अनुमति दिए जाने के बाद, यह अनिवार्य रूप से उस तारीख से संबंधित है जिस दिन शिकायत मूल रूप से दायर की गई थी, और चूंकि वर्तमान मामले में 28

मार्च, 2002 के फैसले द्वारा संशोधन की अनुमति दी गई थी, इसलिए उक्त संशोधन 9 मार्च, 1990 से संबंधित है जब मुकदमा मूल रूप से दायर किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मुकदमा शीर्षक पर आधारित था, और वादी का शीर्षक मूल लिखित बयान के पैराग्राफ 2 में स्वीकार किया गया था, जैसा कि निचली अदालत ने 16 अप्रैल, 2009 के अपने फैसले में माना था। इसलिए उन्होंने कहा कि विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने वर्तमान मामले के तथ्यों पर गलत जारी रखने की याचिका पर जोर नहीं दिया.

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मूल लिखित बयान में वादी के अधिकार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था और उक्त तिथि से तीन साल बीत जाने के बाद, संशोधन स्पष्ट रूप से समय-बाधित था। इसके अलावा, 28 मार्च, 2002 के फैसले में ही यह स्पष्ट किया गया था कि संशोधन की अनुमति परिसीमा की याचिका उठाए जाने के अधीन दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किए गए संशोधन ने नए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का एक पूरी तरह से नया कारण पेश किया और इसलिए किया गया कोई भी संशोधन संभवतः वापस संबंधित नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह का संशोधन स्पष्ट रूप से समय-बाधित होगा।

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। यह विवादित नहीं है कि परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 58 संशोधित वाद पर लागू होगा क्योंकि इसमें स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए पहले से मौजूद राहत में स्वामित्व की घोषणा की राहत को जोड़ने की मांग की गई थी। खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और ए. एन. आर., (2011) 9 एस. सी. सी. 126 में, इस न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 का अर्थ लगाते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"1963 के अधिनियम की अनुसूचित का अनुच्छेद 58, जिसका इस अपील के निर्णय पर असर है, निम्नानुसार हैः

अनुसूचित

परिसीमा की अवधि

[खंड 2 (जे) और 3 देखें]

फर्स्ट डिवीजन-सूट

सूट का विवरण	परिसीमा की अवधि	जिस समय से अवधि शुरू होती है

भाग III-घोषणाओं से संबंधित वाद

58. किसी अन्य घोषणा के लिए	तीन साल	जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है।

परिसीमा अधिनियम, 1908 की अनुसूचित का अनुच्छेद 120 (संक्षेप में "1908 अधिनियम") जिसकी व्याख्या निर्णय में की गई थी श्री रोहतगी द्वारा भरोसा किया गया निर्णय इस प्रकार हैः

मुकदमे की अवधि का विवरण	परिसीमा की अवधि	जिस समय से अवधि शुरू होती है

---

120. सूट जिसके लिए कोई अवधि नहीं है	छह साल	जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है

उपरोक्त दो पुनरुत्पादित लेखों की भाषा से जो अंतर स्पष्ट हैं, वे हैंः

(1) 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत निर्धारित परिसीमा की अवधि छह साल थी जबकि 1963 के अधिनियम के तहत निर्धारित परिसीमा की अवधि तीन साल है और,

(ii) 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत, परिसीमा की अवधि तब शुरू होती है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 58 के तहत निर्धारित अवधि तब शुरू होती है जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 की व्याख्या न्यायिक समिति द्वारा बोलो बनाम कोकलान [(1929-30) 57 IA325: AIR D 1930 PC 270] में की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया थाः (IA p. 331)

मुकदमा करने का कोई अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुकदमे में दावा किए गए अधिकार और उसके उल्लंघन की प्राप्ति न हो, या कम से कम उस प्रतिवादी द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी न हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

इसी विचार को अन्नामलाई चेट्टियार बनाम मुथुकरुप्पन चेट्टियार [आई. एल. आर. (1930) 8 रंग 645] और गोबिंद नारायण सिंह बनाम शाम लाल सिंह [(1930-31) 58 आई. ए. 125] में दोहराया गया था।

रुखमाबाईव बनाम लाला लक्ष्मीनारायण [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 335: (1960) 2 एस. सी. आर. 253], तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के फैसलों पर ध्यान दिया और निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति का सारांश दियाः (रुखमाबाई मामला [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 335: (1960) 2 एस. सी. आर. 253], ए. आई. आर. पी. 349, पैरा 33)

> "33 . ... [1908 अधिनियम] के अनुच्छेद 120 के तहत मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से मुकदमे में वादी द्वारा प्रतिपादित अधिकार का उल्लंघन करने की धमकी दी हो। इस तरह के अधिकार के लिए किसी भी पक्ष द्वारा दी गई हर धमकी, चाहे वह कितनी भी अप्रभावी और हानिरहित क्यों न हो, को एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी नहीं माना जा सकता है ताकि उसे मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जा सके। क्या कोई विशेष खतरा कार्रवाई के अनिवार्य कारण को जन्म देता है, यह इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या वह खतरा प्रभावी रूप से उक्त अधिकार पर आक्रमण करता है या खतरे में डालता है।
>
> 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 58 को अधिनियमित करते समय, विधायिका ने 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 की भाषा को जानबूझकर अलग कर दिया है। "पहले" शब्द का उपयोग "मुकदमा" और "उपार्जित" शब्दों के बीच किया गया है। इसका मतलब यह होगा

कि यदि कोई मुकदमा कार्रवाई के कई कारणों पर आधारित है, तो परिसीमा की अवधि उस तारीख से चलने लगेगी जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकार का लगातार उल्लंघन नए कारण को जन्म नहीं देगा और मुकदमा खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा यदि यह उस दिन से गणना की गई परिसीमा की अवधि से परे है जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित किया गया था।"

14. कानून के इस कथन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वाद का वर्तमान संशोधन वास्तव में इसमें समय-बाधित है. स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने का अधिकार पहली बार 16 मई, 1990 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने विशेष रूप से पैरा 13 में पहले लिखित बयान में अनुरोध किया था कि निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए मुकदमा इस मायने में बनाए रखने योग्य नहीं है कि वादी मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के साथ स्वामित्व स्थापित करने में विफल रहा था। एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है, वह संबंध के सिद्धांत के संबंध में है जहां तक कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू होता है।

15. वर्ष 1900 की शुरुआत में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसानदास रूपचंद बनाम रचप्पा विठोबा, आई. एल. आर. 33 बोर्न 644 (1900) मामले में निम्नलिखित निर्णय दियाः -

"... सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तों को पूरा करते हैं (ए) दूसरे पक्ष के साथ अन्याय न करने की, और (बी) पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होने की। लेकिन मैं आगे अधिकारियों का हवाला

देने से बचता हूं, क्योंकि, मेरी राय में, वे सभी एक ही सिद्धांत निर्धारित करते हैं। वह सिद्धांत, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह है कि संशोधनों को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि अभिवचन मूल रूप से सही था, लेकिन संशोधन से उसे चोट लगेगी जिसकी भरपाई लागत में नहीं की जा सकती थी। यह केवल इस सामान्य नियम का एक विशेष मामला है कि जहां कोई वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में एक नया दावा स्थापित करके संशोधन करना चाहता है, जो कि चूंकि वाद की स्थापना सीमितता से वर्जित हो गई थी, तो संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए; इसकी अनुमति देना प्रतिवादी को ऐसी चोट पहुंचाना होगा जिसकी भरपाई उसे दावे के लिए एक अच्छे बचाव से वंचित करके लागत में नहीं की जा सकती थी। इसलिए अंतिम परीक्षा अभी भी वही हैः क्या संशोधन को दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना अनुमति दी जा सकती है या नहीं? [पृ. 655 पर]"

16. कानून के इस कथन को पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल, 1957 एस. सी. आर. 595, पृष्ठ 603 से 604 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था।

17. बीस साल बाद, चरण दास बनाम अमीर खान, 47 आई. ए. 255 (1920) में प्रिवी काउंसिल ने कानून को इस प्रकार कहाः -

"यह कि संशोधन करने की पूर्ण शक्ति थी, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, और हालांकि एक नियम के रूप में ऐसी शक्ति का

प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जहां प्रभाव किसी प्रतिवादी से एक कानूनी अधिकार को छीनना है जो उसे समय बीतने पर प्राप्त हुआ है, फिर भी ऐसे मामले हैं जहां ऐसे विचार मामले की विशेष परिस्थितियों से अधिक भारी हैं।"

18. कानून के इस कथन को एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डिन स्किनर एंड कंपनी (1957 एससीआर 438, पृष्ठ 450 से 451 पर) में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

19. उपरोक्त मामले में तथ्य यह थे कि वादी ने वाद में बताए गए भौतिक तथ्यों के आधार पर धर्मांतरण के अत्याचार के आधार पर हर्जाने का दावा किया था। निचली अदालतों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिवचन और साक्ष्य के आधार पर ऐसा दावा विफल होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में दलीलों के चरण में, वादी ने तथ्यों के एक ही समूह पर एक वैकल्पिक याचिका दायर करके वाद के संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया, अर्थात् माल की डिलीवरी पर अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा। उस मामले में प्रत्यर्थियों ने संशोधन के लिए उक्त याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कार्रवाई के इस नए कारण पर आधारित मुकदमे को परिसीमा द्वारा बाधित किया जाएगा। इस न्यायालय ने उक्त संशोधन को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए भौतिक तथ्यों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, जो सभी संशोधित अनुरोध के समर्थन में थे। किसी भी मामले में, वाद में प्रार्थना जैसा कि यह मूल रूप से थी, स्वयं सामान्य थी और केवल हर्जाने का दावा करती थी। इस प्रकार, अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के दावे को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी आरोप पहले से ही शिकायत में थे। एकमात्र चीज जिसकी कमी थी वह यह आरोप था कि वादी अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करने के हकदार थे। उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें, एक नियम के रूप में, संशोधनों की अनुमति देने से इनकार कर देंगी, यदि संशोधित दावे पर एक नया मुकदमा आवेदन की तारीख पर परिसीमा द्वारा बाधित किया जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा कारक है जिसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यह न्याय के हित में आवश्यक होने पर इसे आदेश देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।"

20. यह स्पष्ट है कि यह मामला उन मामलों के एक असाधारण वर्ग से संबंधित था, जहां इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी को समय बीतने के साथ एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया था, फिर भी इस विचार को मामले की विशेष परिस्थितियों से अधिक महत्व दिया गया था, अर्थात्, किसी भी नए भौतिक तथ्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, और कानून में मूल याचिका को खारिज किए जाने के मद्देनजर केवल एक वैकल्पिक अनुरोध किया जाना आवश्यक था।

21. 1957 में एस. सी. आर. 595 में रिपोर्ट किए गए पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल के साथ भी ऐसा ही मामला है। यहाँ फिर से यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधन ने वास्तव में कोई नया तथ्य पेश नहीं किया, न ही प्रतिवादी को परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद पहली बार स्थापित किए गए नए दावे को पूरा करना पड़ा

22. के. रहेजा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और अन्र बनाम गठबंधन मंत्रालय और अन्य, 1995 सप. (3) एस. सी. सी. 17, इस न्यायालय को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर एक वाद में संशोधन करने के लिए एक विलंबित आवेदन के साथ जब्त कर लिया गया था। इसे दायर किए जाने के सात साल बाद, अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक याचिका में संशोधन करने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया गया

था। इस आधार पर इस तरह के संशोधन को अस्वीकार करते हुए कि यह समय-बाधित था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः -

> "यह देखा गया है कि अलगाव की अनुमति विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने की पूर्व शर्त नहीं है। विशिष्ट निष्पादन की डिक्री हमेशा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने की शर्त के अधीन होगी। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रत्यर्थियों ने अनुबंध की शर्तों का पालन करने से इनकार कर दिया है, उन्हें मूल मुकदमे में ही विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत मांगनी चाहिए थी। मुकदमा दायर करने की तारीख से सात साल की अवधि को समाप्त होने की अनुमति देने और परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूचित के अनुच्छेद 54 के तहत परिसीमा की अवधि तीन साल होने की अनुमति देने के बाद, निर्धारित आधारों पर कोई भी संशोधन प्रतिवादी को प्राप्त होने वाले परिसीमा के मूल्यवान अधिकार को विफल कर देगा।"

23. इसी तरह, एल. आर. और ए. एन. आर., (2001) 6 एस. सी. सी. 163 के माध्यम से विश्वंभर और अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण (मृत) में, मूल रूप से कब्जे की वसूली के लिए दायर एक मुकदमे में, परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद एक संशोधन करने की मांग की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि कुछ बिक्री विलेखों को अलग कर दिया जाए। इस न्यायालय ने इसे इस प्रकार खारिज कर दियाः

> "अभियोग के निष्पक्ष अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि वादी का मामला जिस मुख्य आधार पर संतुलित था, वह यह था कि उनकी मां-अभिभावक लक्ष्मीबाई द्वारा किए गए अलगाव अमान्य थे और

इसलिए, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था क्योंकि वे कानूनी आवश्यकता और सक्षम अदालत की अनुमति के बिना समर्थित नहीं थे। उस आधार पर, दावा किया गया था कि अलगाव ने वाद संपत्ति में वादी के हित को प्रभावित नहीं किया। वादपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 2 और 4 के बिक्री विलेखों को अलग करने, संबंधित खरीदारों से बेची गई संपत्तियों का कब्जा वसूल करने, वादी की वाद संपत्तियों से हिस्से का अलग कब्जा बनाने वाली संपत्तियों का विभाजन करने और उन्हें वितरित करने की प्रार्थना की गई थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निचली अदालत के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत ने वादी के मामले को स्वीकार किया कि विवाद में अलगाव कानूनी आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं थे। उन्होंने यह भी माना कि उक्त अलगाव के लिए अदालत की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थितियों में, क्या अलगाव शून्य या शून्य हैं? हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 (2) में, यह निर्धारित किया गया है कि प्राकृतिक अभिभावक, अदालत की पूर्व अनुमति के बिना, नाबालिग की अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को बिक्री द्वारा हस्तांतरित नहीं करेगा। उक्त धारा की उप-धारा (3) में, यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि उप-धारा (2) के उल्लंघन में एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा अचल संपत्ति का कोई भी निपटान नाबालिग या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के कहने पर अमान्य है। इसलिए, इस बात में संदेह की बहुत कम गुंजाइश है कि लक्ष्मीबाई द्वारा किए गए अलगाव, जिन्हें मुकदमे में चुनौती दी गई है, वादी के कहने पर अमान्य थे और वादी

को हस्तांतरण से बचने और खरीदारों से संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए अलगाव को अलग करने की आवश्यकता थी। जैसा कि वाद में पहले उल्लेख किया गया है कि संशोधन से पहले बिक्री विलेखों को अलग करने का अनुरोध नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का अनुरोध मुकदमे की सुनवाई के दौरान संशोधन द्वारा पेश किया गया था और निचली अदालत ने संशोधित अनुरोध पर विचार किया और उस आधार पर मुकदमे का फैसला किया। यदि कानूनी रूप से वादी को बेची गई संपत्तियों के संबंध में कोई भी दावा करने से पहले बिक्री विलेखों को अलग रखने की आवश्यकता थी, तो इस तरह के अनुरोध के बिना एक मुकदमा वादी के लिए कोई लाभ नहीं था। सभी संभावनाओं में, इस कठिनाई को महसूस करते हुए वादी ने बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए प्रार्थना पेश करने की मांग करते हुए शिकायत के संशोधन के लिए आवेदन दायर किया। दुर्भाग्य से, एहसास बहुत देर से हुआ। स्वीकार करते हुए, वादी 2 दिगंबर ने 5-8-1975 पर बहुमत प्राप्त किया और वादी 1, विश्वंभर ने 20-7-1978 पर बहुमत प्राप्त किया। हालाँकि मुकदमा 30-11-1980 पर दायर किया गया था, लेकिन बिक्री विलेखों को अलग करने की प्रार्थना दिसंबर 1985 में की गई थी। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 में वार्ड के संरक्षक द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की गई है, उस वार्ड द्वारा जो बहुमत प्राप्त कर चुका है और अवधि की गणना उस तारीख से की जानी है जब वार्ड बहुमत प्राप्त करता है। चूंकि परिसीमा उन तारीखों से शुरू हो गई थी जब वादी ने बहुमत प्राप्त किया था, इसलिए जहां तक दिगंबर

का संबंध है, निर्धारित अवधि वाद प्रस्तुत करने की तारीख तक बीत चुकी थी। इसलिए, त्रि-1 अदालत ने दिगंबर द्वारा दायर मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया। मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के फैसले को उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह मानते हुए भी कि वादी में से एक द्वारा दायर मुकदमा समय के भीतर था, पूरे मुकदमे को परिसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था, दिगंबर द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ चुनौती के अभाव में पहली अपीलीय अदालत निचली अदालत के फैसले के उस हिस्से में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। विश्वंभर द्वारा दायर मुकदमे के संबंध में, यह परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था, लेकिन बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए अनुरोध के बिना। चूंकि अलग की गई संपत्तियों के कब्जे की वसूली का दावा बिक्री विलेखों को अलग किए बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए शुरू में दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था। तारीख (दिसंबर 1985) तक दोष को सुधार लिया गया था और इस तरह की राहत की मांग के लिए परिसीमा की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी। इन परिस्थितियों में, वाद का संशोधन वादी के बचाव में नहीं आ सका वादपत्र के कथनों से, यह नहीं कहा जा सकता है कि लक्ष्मीबाई द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों को अलग करने के लिए सभी आवश्यक कथन वादपत्र में निहित थे और विक्रय विलेखों को अलग करने के लिए विशिष्ट प्रार्थना जोड़ना केवल एक औपचारिकता थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वाद का आधार जो वाद के संशोधन से पहले था, यह था कि लक्ष्मीबाई द्वारा

नाबालिगों के संरक्षक के रूप में किए गए बिक्री लेनदेन शुरू से ही अमान्य थे और इसलिए, उनकी उपेक्षा की जा सकती है। बिक्री विलेखों को अलग रखने के लिए प्रार्थना की शुरुआत करके मुकदमे के आधार को बदलकर संरक्षक द्वारा संपत्ति के अलगाव को अलग करने की मांग की गई। ऐसी परिस्थिति में, स्थानान्तरण को दरकिनार करने के लिए वाद को उस तारीख को दायर किया जा सकता था जिस दिन शिकायत में संशोधन की अनुमति दी गई थी और उससे पहले नहीं।" (पैरा 9 और 10 में)

24. सिद्दलिंगम्मा और अन्र बनाम ममता शेनॉय, (2001) 8 एस. सी. सी. 561 में, इस न्यायालय ने मकान मालिक की प्रामाणिक आवश्यकता के मामले में वाद के संशोधन की अनुमति देते हुए कहा कि संबंध वापसी का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत किए गए सभी संशोधनों पर लागू होगा, जो आम तौर पर अभिवचनों के संशोधन को नियंत्रित करता है, जब तक कि अदालत किसी दिए गए मामले में ऐसे सिद्धांत की प्रयोज्यता को बाहर करने का कारण नहीं देती है। उस मामले में तथ्यों पर परिसीमा का कोई सवाल नहीं उठाया गया था, जो इसलिए उन मामलों की श्रेणी में होगा जो निर्णयों की पंक्ति का पालन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि लागत आमतौर पर देरी से किए गए संशोधन की भरपाई कर सकती है, लेकिन परिसीमा की अवधि के भीतर, यह एक असाधारण मामला नहीं है जैसा कि दो निर्णयों एल. जे. लीच एंड कंपनी में निहित है। लिमिटेड और पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल ऊपर उद्धृत किए गए हैं।

25. सैम पथ कुमार बनाम अय्याकन्नु और अन्र., (2002) 7 धारा 559 में, इस न्यायालय को स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे को संशोधन के माध्यम से स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए एक मुकदमे में

परिवर्तित करने के लिए वाद की स्थापना की तारीख के 11 साल बाद किए गए संशोधन के लिए एक आवेदन का सामना करना पड़ा। इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

> "हमारी राय में, प्रस्तावित संशोधन द्वारा मुकदमे की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसे बदलने की मांग की गई है वह वादी द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति है। निचली अदालत की राय में, वादी के लिए एक नया मुकदमा दायर करना खुला था और यह उन कारणों में से एक है जो निचली अदालत और उच्च न्यायालय के साथ संशोधन के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने और वादी के संशोधन को खारिज करने में भी प्रबल रहा है। हम यह समझने में विफल हैं कि यदि वादी के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने की अनुमति है, तो उसी राहत को लंबित मुकदमे में शामिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए एक नए मुकदमे में अनुरोध किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संशोधन की अनुमति देने से कानूनी कार्यवाही की बहुलता में कमी आएगी।
>
> आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. अदालत को कार्यवाही के किसी भी चरण में और ऐसी शर्तों पर अपनी दलीलों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जो न्यायसंगत हो। ऐसे संशोधन जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को प्रस्तुत करने और उनका निर्धारण करने के लिए निर्देशित किए जाते हैं, उन्हें करने की अनुमति दी जाएगी। संशोधन के लिए आवेदन पेश करने में देरी के प्रश्न का निर्णय केवल वाद की स्थापना की तारीख से अवधि की गणना करके नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि

उस चरण के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिस पर वाद में सुनवाई आगे बढ़ी है। मुकदमे के शुरू होने के बाद या उसके समापन के बाद किए जाने वाले संशोधनों की तुलना में मुकदमे से पहले के संशोधनों को अधिक उदारता से अनुमति दी जाती है। पूर्व मामले में आम तौर पर यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है क्योंकि उसे वादी के मामले को संशोधित करने का पूरा अवसर मिलेगा। बाद के मामलों में विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह का सवाल उठ सकता है और इसका जवाब प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में देना होगा। कोई स्ट्रैट जैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि संशोधन के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए केवल देरी एक आधार नहीं हो सकती है।

एक बार शामिल किया गया संशोधन मुकदमे की तारीख से संबंधित है। हालाँकि, अभिवचनों के संशोधन के संदर्भ में संबंध-वापसी का सिद्धांत सार्वभौमिक अनुप्रयोग में से एक नहीं है और उपयुक्त मामलों में न्यायालय संशोधन की अनुमति देते समय यह निर्देश देने में सक्षम है कि उसके द्वारा अनुमत संशोधन मुकदमे की तारीख से संबंधित नहीं होगा और उसके द्वारा अनुमत परिसीमा तक यह माना जाएगा कि उस तारीख को अदालत के समक्ष लाया गया था जिस दिन संशोधन की मांग करने वाला आवेदन दायर किया गया था। (सिद्दलिंगम्मव में टिप्पणियाँ देखें। ममता शेनॉय [(2001) 8 एस. सी. सी. 561]

वर्तमान मामले में मुकदमा दायर होने की तारीख के लगभग 11 साल बाद से संशोधन की मांग की जा रही है। वादी को उन बुनियादी तथ्यों पर स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली की राहत की मांग करने वाला एक नया मुकदमा शुरू करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, जैसा कि स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा जारी करने की राहत की मांग करने वाले वाद में अनुरोध किया गया है और जो लंबित है। मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए लंबित मुकदमे में स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली की राहत की अनुमति देना विवेक का एक अच्छा अभ्यास होगा। वादी ने आरोप लगाया है कि राहत के लिए कार्रवाई का कारण अब जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि मुकदमा लंबित रहने के दौरान उसके सामने आया था। संशोधन के माध्यम से शामिल किए जाने वाले कथनों के गुणों को संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति देने के चरण में नहीं आंका जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी यह प्रस्तुत करने में सही है कि यदि उसने पहले ही प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को पूर्ण कर लिया है, तो इस तरह से अर्जित अधिकार को एक संशोधन की अनुमति देकर और एक नई राहत की मांग करके पराजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो मुकदमे की तारीख से संबंधित होगी और इस तरह प्रतिवादी को समय बीतने पर उसे अर्जित लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अर्जित किए गए अभिनिर्धारित अधिकार की अवधि की गणना में लगभग 11 साल की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतिवादी के हित की रक्षा यह निर्देश देकर की जा सकती है कि जहां तक स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली का

संबंध है, उस संबंध में प्रार्थना उस तारीख को की गई मानी जाएगी जिस दिन संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया है।"

26. यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले के तथ्यों पर संशोधन की अनुमति परिसीमा की याचिका के अधीन दी गई थी जिसे प्रतिवादी द्वारा मामले में मुकदमे के आगे बढ़ने पर लिया जा सकता था।

27. वन विभाग कर्मचारी गृह निर्माण संस्था मर्यादा (पंजीकृत) बनाम रमेश चंदर और अन्य (2010) 14 एस. सी. सी. 596 में, इस न्यायालय ने एक मुकदमे पर विचार किया जो मूल रूप से भूमि के स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था। यह मुकदमा 11 फरवरी, 1991 को दायर किया गया था। 16 दिसंबर, 2002 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत को शामिल करने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया गया था। इस न्यायालय ने मुकदमे में किए गए मध्यप्रवाह परिवर्तन को बिना किसी अनिश्चित शर्त के अस्वीकार कर दिया और कहाः -

"वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है और अपीलकर्ताओं ने परिसीमा की अवधि के भीतर पहले प्रतिवादी के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। इस संदर्भ में, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 का प्रावधान बहुत प्रासंगिक है। विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए अनुच्छेद 54 में निर्धारित परिसीमा की अवधि निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि से तीन साल है, या यदि ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं है, जब वादी को नोटिस है कि निष्पादन से इनकार कर दिया गया है।

यहाँ स्वीकार किया जाता है कि 1976 में पक्षों के बीच किए गए बिक्री समझौते में प्रदर्शन के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन निश्चित रूप से अपने दिनांकित 3-2-1991 के नोटिस द्वारा, पहले प्रतिवादी ने समझौते के प्रदर्शन को अस्वीकार करने के बारे में अपने इरादे स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिए हैं और समझौते को रद्द कर दिया है।

भले ही विशिष्ट निष्पादन की राहत को शामिल करने के लिए संशोधन का अनुरोध मुकदमा दायर करने के लगभग 11 साल बाद किया गया था, और मुकदमा दायर करने के 12 साल बाद इसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के तहत स्पष्ट प्रतिबंध को देखते हुए मामले के तथ्यों में ऐसा संशोधन मूल शिकायत दायर करने की तारीख से संबंधित नहीं हो सकता है। यहाँ इस मामले में, संशोधन के माध्यम से विशिष्ट निष्पादन की याचिका को शामिल करने से मुकदमे का स्वरूप वस्तुतः बदल जाता है, और इसका आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था और शिकायत को एक अलग अदालत में स्थानांतरित करना पड़ा था। यह न्यायालय विश्वंभर्व में आयोजित हुआ। लक्ष्मीनारायण [(2001) 6 एस. सी. सी. 163], यदि संशोधन की अनुमति देने के परिणामस्वरूप, वाद का आधार बदल दिया जाता है, तो इस तरह के संशोधन की अनुमति होने के बावजूद, परिसीमा के दोष को ठीक करने के लिए वाद दायर करने की तारीख से संबंधित नहीं हो सकता है। वे सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होते हैं।" (पीपी. 168-69, पैरा 9 पर एससीसी)। [पैरा 24,25 और 32 में]

28. पृथ्वी पाल सिंह और अन्र बनाम अमरीक सिंह और अन्य, (2013) 9 धारा 576 में, यह न्यायालय पंजाब पूर्व-मुक्ति अधिनियम, 1913 के तहत पूर्व-मुक्ति का दावा करने वाले मुकदमे से संबंधित था। वाद में एक संशोधन की मांग की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि वादी वाद संपत्ति के सह-हिस्सेदार के रूप में राहत का हकदार था। इस न्यायालय ने अपने पहले के कुछ निर्णयों पर विचार करने के बाद कहाः -

> "हमारी राय में, विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि प्रतिवादी 2 द्वारा दायर संशोधन के लिए आवेदन को बिना किसी शर्त के अनुमति दी गई थी। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि इस न्यायालय का विचार था कि वाद में संशोधन मुकदमा दायर करने की तारीख से संबंधित होगा। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वतंत्र रूप से परिसीमा के मुद्दे पर विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि संशोधित वाद समय द्वारा वर्जित नहीं था।"

29. इस न्यायालय द्वारा इस मामले के तथ्यों पर इस प्रकार निर्धारित कानून को लागू करने से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले, 16 मई, 1990 के मूल लिखित बयान में, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वादी को नोटिस पर रखा था कि उसने वाद संपत्ति पर वादी के अधिकार से इनकार कर दिया था। इस मामले के तथ्यों पर निचली अदालत द्वारा लिखित बयान में एक पृथक पैरा, अर्थात् पैरा 2 को पढ़ने पर उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत दिए गए फैसले में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। समग्र रूप से पढ़ा गया मूल लिखित बयान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी ने वादी के शीर्षक को स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, संशोधन की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने 28 मार्च, 2002 के अपने पहले के फैसले में मामले को स्पष्ट रूप से निचली अदालत में भेज दिया था, जिससे प्रतिवादी को परिसीमा की याचिका उठाने की अनुमति मिल गई

थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के एक आवेदन पर, स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने का अधिकार पहली बार 16 मई, 1990 को वर्तमान मामले के तथ्यों पर उत्पन्न हुआ, जब मूल लिखित बयान ने स्पष्ट रूप से वादी के अधिकार का खंडन किया। इसलिए 16 मई, 1993 तक स्वामित्व की घोषणा पर आधारित मुकदमा समय-बाधित हो जाता। यह स्पष्ट है कि संबंध वापसी का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर इस कारण से लागू नहीं होगा कि जिस न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी थी, उसने स्पष्ट रूप से इसे परिसीमा की याचिका के अधीन अनुमति दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान मामले में संबंध वापसी के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई विशेष या असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं ताकि प्रतिवादी के पक्ष में अर्जित कानूनी अधिकार को छीन लिया जाए। ऐसा होने के कारण, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। तदनुसार वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।